भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2649

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआईसीडीपी

2649. श्री बी. के. पार्थसारथी:

श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों और स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या का वर्ष वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का परियोजना वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एनआईसीडीपी के अंतर्गत जारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और भौतिक प्रगति का ब्यौरा क्या है, साथ ही उनके पूरा होने की समय-सीमा क्या है और विलंब, यदि कोई हो, के कारण क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित किए गए औद्योगिक नोड्स, संभारतंत्र हब, परिवहन संपर्क और यूटिलिटीज जैसे अवसंरचनात्मक घटकों का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा परियोजना के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से बनाए गए विशेष प्रयोजन माध्यमों से औद्योगिक टाउनशिप का विकास शुरू किया है। परियोजना विकास कार्यकलापों में राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार औद्योगिक नोड्स की पहचान, तत्पश्चात परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करने से पहले राज्य सरकार द्वारा संकल्पना मास्टर प्लान और विकास योजना, पर्यावरणीय मंजूरी और विस्तृत डिजाइन योजना तैयार करना और उसका अनुमोदन करना शामिल है। राज्य सरकार का योगदान भूमि के रूप में और भारत सरकार का योगदान इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में होता है।

भारत सरकार ने एनआईसीडीपी के तहत कुल 20 औद्योगिक नोड्स को अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें से 12 परियोजनाओं को पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुमोदित किया गया था। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में है।

(ख): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) को 16,172.95 करोड़ रुपए की निधि संस्वीकृत और जारी की है। एनआईसीडीआईटी ने एनआईसीडीपी के तहत विभिन्न औद्योगिक नोड्स/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना विकास करने हेतु परियोजना एसपीवी को 14,569.97 करोड़ रुपए की निधि जारी की है।

एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए परियोजना एसपीवी को जारी की गई निधि का राज्य और परियोजना-वार विवरण **अनुबंध-II** में है।

(ग): एनआईसीडीपी के तहत अनुमोदित 20 परियोजनाओं में से, चार परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। एनआईसीडीपी के तहत जारी परियोजनाओं (संख्या 16) की वर्तमान स्थिति **अनुबंध-III** में है। इन परियोजनाओं को पूरा करने की कुल निर्माण अवधि, ईपीसी संविदाकार की वास्तविक नियुक्ति की तारीख से 36 से 48 माह है।

(घ): औद्योगिक शहर/नोड के भीतर सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज और विद्युत वितरण सहित आंतरिक मुख्य अवसंरचना को संबंधित परियोजना एसपीवी द्वारा नियुक्त ईपीसी संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। बल्क जलापूर्ति, विद्युत, दूरसंचार और सड़कों जैसी बाह्य कनेक्टिविटी अवसंरचना को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर व्यापक रूप से मैप किया गया और जांच की गई है तथा राज्य विभाग/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से एसएचए/एसएसए की शर्तों के अनुसार संबंधित राज्य एसपीवी द्वारा शुरू किया गया है।

04 पूर्ण परियोजनाओं में निम्नलिखित घटकों को विकसित किया गया हैं:

क्रम सं.	**राज्य**	**नोड**	**विकसित किए गए अवसंरचना घटक**
i.	गुजरात	धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर)	• सड़क और सेवाएं • प्रशासनिक भवन • जल प्राप्त करने की प्रक्रिया और ट्रांसमिशन • जल शोधन संयंत्र • सीवेज शोधन संयंत्र
ii.	महाराष्ट्र	शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए)	

(iii)	उत्तर प्रदेश	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप - ग्रेटर नोएडा (आईआईटी-जीएन)	• सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र • विद्युत अवसंरचना • सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाएं
(iv)	मध्य प्रदेश	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप - विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी-वीयूएल)	

(ङ): कार्य के कार्यान्वयन में तेजी लाने और परियोजनाओं को समय से पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

- शीर्ष निगरानी प्राधिकरण समय-समय पर एनआईसीडीआईटी कार्यकलापों और औद्योगिक कॉरिडोर की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।
- डीपीआईआईटी, एनआईसीडीआईटी के माध्यम से समय-समय पर राज्य सरकार या संबंधित एजेंसियों/हितधारकों के अधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं के विकास की निगरानी करता है।
- जोखिम को कम करने के लिए हितधारकों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके सभी आवश्यक विनियामक और सांविधिक मंजूरी समय पर प्राप्त की जाती है।
- विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जाती है और जहां आवश्यक हो अपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं।
- प्रगति और पीएमजी पोर्टलों का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और जहां भी आवश्यक हो बाधाओं को दूर कर समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाता है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**राज्य**	**नाम**	**परियोजना अनुमोदन वर्ष**
1	उत्तराखंड	खुरपिया में आईएमसी	अगस्त, 2024
2	पंजाब	राजपुरा में आईएमसी	
3	महाराष्ट्र	दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र	
4	केरल	पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र	
5	राजस्थान	जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र	
6	हरियाणा	हिसार में आईएमसी	
7	उत्तर प्रदेश	आगरा में आईएमसी	
8		प्रयागराज में आईएमसी	
9	बिहार	गया में आईएमसी	
10	आंध्र प्रदेश	ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र	
11		कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र	
12	तेलंगाना	जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र	

*****

अनुबंध-II

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**राज्य**	**नाम**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**जारी निधि (करोड़ में)**
1	गुजरात	धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर)	2784	इक्विटी-2784
2	महाराष्ट्र	शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए)	7947	इक्विटी - 3000
		दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र	5469	इक्विटी - 701.13
3	उत्तर प्रदेश	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप - ग्रेटर नोएडा (आईआईटी-जीएन)	1714	इक्विटी - 617.20
		मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) दादरी और बोराकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)	3907	इक्विटी - 853.05
		प्रयागराज में आईएमसी	658	इक्विटी - 323.09
		आगरा में आईएमसी	1812	इक्विटी - 2.50
4	मध्य प्रदेश	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप - विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी-वीयूएल)	808	इक्विटी - 55.93
				ऋण - 83.70
5	हरियाणा	एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब - नांगल चौधरी (आईएमएलएच-एनसी)	1029	इक्विटी - 211.63
				ऋण - 212.15
		हिसार में आईएमसी	4,680	इक्विटी - 2.45
6	राजस्थान	जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर (जेपीएमआईए)	922	इक्विटी - 327.69
7	आंध्र प्रदेश	कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र	2,139	इक्विटी - 533.86
		ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र	2,786	इक्विटी - 500.26

		कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र	2,136	इक्विटी - 500.20
8	कर्नाटक	तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र	1,701	इक्विटी - 586.74
9	केरल	पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र	3,805	इक्विटी - 936.96
10	उत्तराखंड	खुरपिया फार्म में आईएमसी	1,265	इक्विटी - 405.46
11	पंजाब	राजपुरा पटियाला में आईएमसी	1,367	इक्विटी - 215.60
12	बिहार	गया में आईएमसी	1,339	इक्विटी - 134.72
13	तेलंगाना	जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र	2,360	इक्विटी - 536.23

*****

अनुबंध-III

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**परियोजना का नाम और कॉरिडोर**	**क्षेत्र (एकड़)**	**स्थिति**
1	कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश - सीबीआईसी	2,006	ईपीसी संविदाकार की नियुक्ति फरवरी 2024 में की गई
2	तुमकुरु, कर्नाटक - सीबीआईसी	1,736	ईपीसी संविदाकार की नियुक्ति फरवरी 2023 में की गई 250 एकड़ के 06 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं।
3	इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब – नांगल चौधरी (आईएमएलएच-एनसी), हरियाणा - डीएमआईसी	886	परियोजना को पीपीपी आधार पर निष्पादित किया जाएगा। बाह्य कनेक्टिविटी कार्य (सड़क, विद्युत और बाहरी रेल संपर्क) पूरे हो गए हैं। जुलाई, 2025 में पीपीपीएसी द्वारा परियोजना का आकलन किया गया। सभी पटरियों की फिटनेस की जांच करने के लिए लोकोमोटिव ट्रायल रन जून 2026 में पूरा हो गया है।
4	मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच)- उत्तर प्रदेश - डीएमआईसी	825	पीपीपी आधार पर परियोजना निष्पादित की जाएगी। जुलाई 2026 में रियायतकर्ता की नियुक्ति के लिए निविदा फिर से जारी की गई।
	मल्टी मॉडल परिवहन हब (एमएमटीएच) - बोराकी, उत्तर प्रदेश – डीएमआईसी	358	परियोजना को दिसंबर 2024 में रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया बोराकी स्टेशन के लिए इंजीनियरिंग स्केल प्लान (ईएसपी) - मास्टर प्लान, लागत अनुमान, ईपीसी संविदाकार की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए मई, 2025 में एनसीआर द्वारा विकास को मंजूरी दी गई।
5	दिघी, महाराष्ट्र - डीएमआईसी	6,056	एसएचए और एसएसए का निष्पादन: पूर्ण हो गया एसपीवी का निगमन: पूर्ण हो गया है।
6	जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर	1,577	

	(जेपीएमआईए) - राजस्थान		प्रयागराज को छोड़कर नए शहरों (पीएमएनसी) के कार्यक्रम प्रबंधक को शामिल किया गया। ईपीसी को 10 परियोजनाओं के लिए शामिल किया गया।
7	राजपुरा, पंजाब - एकेआईसी	1,099	
8	खुरपिया, उत्तराखंड - एकेआईसी	1,002	
9	प्रयागराज,उत्तर प्रदेश - एकेआईसी	351	
10	गया, बिहार - एकेआईसी	1,670	
11	कोप्पर्थी, आंध्र प्रदेश - वीसीआईसी	2,595	
12	ओरवाकल, आंध्र प्रदेश प्रदेश - एचबीआईसी	2,621	
13	जहीराबाद, तेलंगाना - एचएनआईसी	3,245	
14	पलक्कड़, केरल – सीबीआईसी एक्सटेंशन।	1,710	
15	हिसार, हरियाणा - एकेआईसी	2,988	एसएचए और एसएसए का निष्पादन: पूर्ण एसपीवी का निगमन: पूर्ण पीएमएनसी को शामिल कर लिया गया है।
16.	आगरा, उत्तर प्रदेश - एकेआईसी	1,058	ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) के अंतर्गत आने के कारण सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूरी प्रतीक्षित है।

*****